



उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.  
मुख्यालय, 2-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पीबीएक्स

0522-4151203

फैक्स  
ई.मेल

0522-2629284  
upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / 2024-25 / एफ-312/445

दिनांक : 31 जनवरी, 2025

शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक,  
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,  
समस्त शाखायें, उ0प्र0।

बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक-02.12.2024 में पारित प्रस्ताव सं0-18 के  
क्रम में बैंक में कृषि अवसंरचना निधि योजना (Agriculture Infrastructure Fund scheme)  
निम्नवत् लागू की जाती है:-

#### कृषि अवसंरचना निधि योजना:-

1. योजना का नाम	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि अवसंरचना कोष (ए0आई0एफ0) योजना।</li> <li>यह योजना वर्तमान में 2032-33 तक लागू है।</li> </ul>
2. उद्देश्य	<p>देश में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोत्तर प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।</p> <p>(To mobilize a medium-long term debt financing facility for investment in viable projects for post harvest management infrastructure and community farming assets through incentives and financial support in order to improve agriculture infrastructure in the country)</p>
3. ऋण की अवधि एवं वसूली	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिकतम 07 वर्ष (02 वर्ष की मेराटोरियम अवधि को सम्मिलित करते हुए) मेराटोरियम की अवधि न्यूनतम 06 माह से अधिकतम 02 वर्ष की हो सकती है। (ऋण को वसूली योजना की समाप्ति अवधि तक अवश्य हो जाना चाहिए अन्यथा की स्थिति में सब्सिडी देय नहीं होगी क्योंकि वर्तमान में 2032-33 तक ही योजना लागू है)</li> <li>ऋण की वसूली समान मासिक किस्तों में की जाएंगी।</li> <li>मेराटोरियम अवधि में मासिक ब्याज ऋणी से जमा कराया जायेगा।</li> </ul>
4. ब्याज की दर	9 प्रतिशत (समय-समय पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फार्मर्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार)

<p>5. पात्र उधारकर्ता</p>	<p>ए0आई0एफ0 के तहत पात्र उधारकर्ता</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply chain services including e-marketing platforms</li> <li>• Warehouse &amp; Silos</li> <li>• Cold Stores and Cold Chain</li> <li>• Packaging Units</li> <li>• Assaying Units</li> <li>• Sorting and grading units</li> <li>• Logistic Facilities- Reefer Van &amp; Insulated vehicles</li> <li>• Ripening Chambers</li> <li>• Farm residue/waste management infrastructures</li> <li>• Primary Processing activities* (See table 1)</li> <li>• Integrated primary and secondary processing activities**(See table1)</li> </ul> <p><b>Viable Farming Assets</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organic inputs production – Vermicomposting etc.</li> <li>• Compressed Biogas ( CBG) Plant</li> <li>• Bio stimulant production units</li> <li>• Infrastructure for smart and precision agriculture - Purchase of drones, boom sprayer, putting up specialized sensors on field, Blockchain and AI in agriculture etc. ,Remote sensing and Internet of Things (IOT) such as automatic weather station, Farm advisory services through GIS applications.</li> <li>• Nursery</li> <li>• Tissue culture</li> <li>• Seed Processing</li> <li>• Custom Hiring Center –farm machinery/ implements ( minimum of 4 in quantity)</li> <li>• Farm/Harvest Automation (combine harvester, sugarcane harvester etc.)</li> <li>• Setting up of Decentralized Ground/ Stilt Mounted</li> </ul>
---------------------------	--

	<p>Grid Connected Solar based Power Plants (PM-KUSUM component A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standalone solar pumping system (PM-KUSUM component B)</li> <li>• Solarization of grid connected agri-pump under PM-KUSUM component C</li> <li>• Integrated Spirulina production &amp; processing units</li> <li>• Sericulture processing unit</li> <li>• Honey processing</li> <li>• Plant quarantine units</li> <li>• Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.</li> <li>• Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building viable farming assets or post-harvest management projects.</li> <li>• Hydroponic Farming</li> <li>• Mushroom farming Vertical farming</li> <li>• Aeroponic farming</li> <li>• Poly house/ Greenhouse</li> <li>• Logistics facilities (including non-refrigerated/insulated vehicles) (Not eligible for individuals/Farmers)</li> <li>• Tractor (Not eligible for individuals/Farmers)</li> </ul> <p><b>Note 1:</b> Solarization of any of the eligible infrastructure can also be financed under AIF.</p> <p><b>Note 2:</b> Digital Connectivity and optic fiber infrastructure shall be eligible investment as part of development of the aforementioned eligible</p>
--	---

	<p>projects. <b>Note 3:</b> Component-A of PM-KUSUM eligible for Individual farmers/ Group of farmers/ FPOs/ Cooperatives/ Panchayats to set up solar power plants of capacity up to 2 MW on barren/ cultivable/ uncultivable/ pasturelands or marshy lands.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Department of Agriculture &amp; Farmers Welfare</b> <b>Ministry of Agriculture &amp; Farmers Welfare Government of India</b> द्वारा योजना से सम्बन्धित Revised दिशा निर्देशों के अनुसार</li> <li>● या एआईएफ योजना के अन्तर्गत वह पात्र क्षेत्र जिनको भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी गयी हो।</li> </ul>
6. पात्र उधारकर्ता के चयन के लिए मानदंड	<p>अ) <b>व्यक्तिगत कृषक/उद्यमी</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदन की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच है। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तो आवेदक के सभी उत्तराधिकारी पुत्र/पुत्रों/पुत्री/पुत्रीयों एवं पति/पत्नी/ को सह-आवेदक बनाकर योजना का लाभ दिया जा सकता है।</li> <li>2. बंधक रखी जाने वाली सम्पत्ति पर अन्य किसी बैंक/संस्था का भार नहीं होना चाहिए।</li> <li>3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त क्रेडिट इन्फोरमेशन कम्पनी (सी0आई0सी0) के द्वारा प्रार्थी आवेदक का क्रेडिट स्कोर 700 से कम नहीं हो।</li> <li>4. एआईएफ यूनिट हेतु ऋण लेने वाले व्यक्तियों, ऋण लेने वाली फर्म दोनों का ही सिबिल स्कोर प्राप्त किया जायेगा। ऋणी/ऋणियों का सिबिल स्कोर 700 से नीचे नहीं होना चाहिए तथा ऋण लेने वाली फर्म का सिबिल एमएसएमई रैंक (सीएमआर) 01 से 6 तक है तो ऋण अनुमन्य किया जायेगा। यदि 06 से ऊपर है तो ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।</li> <li>5. नये उद्यमियों हेतु Finance Income and Trade Rank (फिट रैंक) देखी जायेगी। फिट रैंक की गणना ऋणी के बैंक स्टेटमेण्ट, आईटीआर एवं जीएसटी रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा फिट रैंक 01 से 06 तक होगी तो ऋण स्वीकृत किया जायेगा यदि फिट रैंक 06 से ऊपर होगी तो ऋण स्वीकृत नहीं किया</li> </ol>



	<p>जायेगा।</p> <p>6. नये उद्यमियों के मामलों में जहां सीएमआर रैंक नहीं है वहां पर Finance Income and Trade Rank (फिट रैंक) के साथ-साथ फर्म आदि के डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराईटर की सिबिल स्कोर रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा जिन ऋणियों की सिबिल स्कोर नहीं आ रही है ऐसे मामलों में उनका एनटीसी स्कोर के आधार पर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जायेगा।</p> <p>7. यदि नये ऋणियों का New To Credit (एनटीसी) स्कोर 131 या उससे ऊपर है तो बैंक ऋण स्वीकृत करेगा एवं यदि 131 से नीचे है तो ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।</p> <p>8. के0वाई0सी0 डाक्यूमेण्ट</p> <p>9. ऋण अवधि हेतु डीपीआर</p> <p>10. प्रोजैक्टड बैलेन्स शीट</p> <p>11. उद्यम रजिस्ट्रेशन</p> <p>12. यदि पूर्व से व्यवसाय किया जा रहा है तो पूर्व वर्षों की बैलेन्सशीट तथा व्यवसायिक लाभ होना चाहिए।</p> <p>13. विगत 03 वर्षों का आईटीआर, यदि व्यवसाय 03 वर्षों से किया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में 02 वर्ष या 01 वर्ष का भी आईटीआर लिया जा सकता है। यदि ऋणी नया है तो आईटीआर की आवश्यकता नहीं।</p> <p>14. यदि नई परियोजना लगाई जा रही है तो आईटीआर की आवश्यकता नहीं है।</p> <p><b>(ब) संस्था/निगम/संघ/एजेन्सी/एफपीओ</b></p> <p>1. आवेदक संस्था आदि सम्बन्धित अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।</p> <p>2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान लाभ अर्जित किया है।</p> <p>3. आडिट या अन्य रेग्युलेटरी कम्पलाईन्सेस पूर्ण होनी चाहिए।</p> <p>4. पेशेवर प्रबंधन हो।</p> <p><b>(स) स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह</b></p> <p>1. समूह कम से कम छः माह से सक्रिय होना चाहिए।</p> <p>2. अपने संसाधनों से बचत की हो और ऋण दिया हो।</p> <p>3. ऋण अवधि के डीपीआर</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. प्रोजेक्टेड बैलेन्स शीट</li> <li>5. यदि पूर्व से व्यवसाय किया जा रहा है तो पूर्व वर्षों की बैलेन्सशीट तथा व्यवसायिक लाभ होना चाहिए।</li> <li>6. समुचित खाते एवं रिकार्ड सुरक्षित रखा हो।</li> <li>7. लोकतांत्रिक तरीके से काम होना, व होते हुए दिखना चाहिए जहां सभी सदस्यों की सुनी जानी चाहिए।</li> <li>8. स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह एक दूसरे की सहायता करने और मिलाकर काम करने के लिए बनाया गया होना चाहिए और बैंक इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिए कि समूह का गठन केवल प्रोजेक्ट में भाग लेने और उसके लाभ प्राप्त करने के लिए ही नहीं बनाया गया है।</li> <li>9. सदस्यों की पृष्ठभूमि और हित एक समान होने चाहिए।</li> <li>10. समूह पंच सूत्र का पालन कर रहा है पंच सूत्र-नियमित मिटिंग, नियमित बचत, नियमित आंतरिक ऋण, ऋण का समय पर पुनर्भुगतान और अप टु डेट बुक्स ऑफ अकाउण्ट रिकार्ड का रख-रखाव।</li> <li>11. एफपीओ होने के लिए बैंक द्वारा निर्गत एफपीओ पालिसी या एफपीओ होने के लिए भारत सरकार द्वारा पात्र एफपीओ।</li> </ol>
7. ऋण की धनराशि	<p>रु0 60.00 लाख,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋणी/उद्यमी/फर्म के द्वारा प्लान्ट मशीनरी हेतु ऋण कोटेशन जिस फर्म या संस्था से प्राप्त किये जायेंगे उन्हीं के खाते में बैंक प्लान्ट, मशीनरी आदि खरीदने हेतु सीधे धनराशि अंतरित करेगा।</li> </ul>
8. सीमा की प्रकृति	सावधि ऋण (टर्म लोन)
9. साख सीमा का निर्धारण, ऋण की मात्रा एवं एक्सपोजर नार्मस	<p>आवश्यकता आधारित। सीमा परियोजना लागत और परियोजना के कुल वित्तीय परिव्यय के आधार पर तय की जाएगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. इस योजना के तहत परियोजना पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने पर अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 80% या बैंक एक्सपोजर नार्मस के अंतर्गत निर्धारित सीमा राशि तक, जो भी दोनो में कम हो, ऋण स्वीकृति के लिए पात्र अधिकतम सीमा राशि होगी।</li> </ol>

	<p>2. स्वयं सहायता समूह के आंकलन के अनुमान बचत एवं ऋण का स्वीकार्य अनुपात सामान्यतः 1:1 से 1:4 हो सकता है। परन्तु ऋण उद्देश्य एवं समूह की ग्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए यह अनुपात अधिक भी हो सकता है।</p>
10. मार्जिन मनी/ लाभार्थी अंशदान	परियोजना लागत का न्यूनतम 20% प्रमोटर के योगदान के रूप में अनिवार्य होगा।
11. ऋण की सुरक्षा	<p><b>प्राथमिक सुरक्षा</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बैंक के ऋण से जो सम्पत्ति/आस्ति/मशीन आदि सृजित की जायेगी उसे दृष्टिबंधक/प्राथमिक सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा। भूमि और भवन को भी गिरवी रखा जायेगा यदि सीजीटीएमएससी गारण्टी ऋणी द्वारा नहीं ली गयी है या एफपीओ के मामले में नैब संरक्षण गारण्टी नहीं ली गयी है। सीजीटीएमएसई गारण्टी/नैब संरक्षण गारण्टी के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेंगे उनमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी या प्रमोटर्स/थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी। अन्य मामलों में प्रमोटर्स गारण्टी/थर्ड पार्टी गारण्टी ली जायेगी।</li> <li>• उक्त योजना हेतु सीजीटीएमएसई गारण्टी फीस सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। अतः सीजीटीएमएसई गारण्टी फीस ऋणी से नहीं ली जायेगी।</li> <li>• एफपीओ के मामले में नैब संरक्षण प्रा0 लि0 द्वारा गारण्टी कवर प्रदान किया जायेगा।</li> <li>• सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर 05 वर्ष हेतु दिया जायेगा, जिसे 05 वर्ष के बाद मोडीफाई करके 02 वर्ष अतिरिक्त गारण्टी कवर प्रदान किया जा सकेगा। इस प्रकार 07 वर्षों हेतु गारण्टी कवर उपलब्ध होगा।</li> </ul> <p><b>संपाश्विक सुरक्षा (Collateral Security)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• जो ऋणी सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर नहीं लेना चाहता उससे कोलेटील सिक्योरिटी ली जायेगी तथा ऐसी सिक्योरिटी को साम्य बन्धक भी कराया जायेगा। इस हेतु निर्धारित धनराशि के स्टाम्प पेपर पर साम्य बन्धक कराया जायेगा।</li> <li>• संपाश्विक सुरक्षा हेतु ऋण राशि के डेढ़ गुना मूल्य की अचल सम्पत्ति अथवा भवन या भवन साम्य बन्धक के रूप में लिया जायेगा।</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>● स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह आवेदकों के मामले संपाश्विक पर प्रतिभूति (Collateral Security) के लिए कोई आग्रह नहीं।</li> <li>● सम्पत्ति का मूल्यांकन (Valuation) रजिस्टर्ड वेल्थूतर द्वारा कराना आवश्यक है।</li> <li>● अगर कृषि क्षेत्र की गतिविधि है तो राजस्व रिकॉर्ड में चार्ज सृजित कर कृषि भूमि को गिरवी रखना होगा।</li> <li>● कोलेट्रल सिक्योरिटी के विरुद्ध स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों में मालिकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/निवेशकों आदि की व्यक्तिगत गारण्टी ली जायेगी।</li> <li>● दो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों की भी गारण्टी कोलेट्रल ऋणों हेतु ली जायेगी, किन्तु सीजीटीएमएसई गारण्टी के अन्तर्गत 02 व्यक्तियों की गारण्टी नहीं ली जायेगी।</li> </ul>						
12. सेवासुलक/प्रसंस्करण आदि सुलक	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बैंक द्वारा एमएसएमई क्षेत्र हेतु निर्धारित दरें प्रभावी होंगी। प्रशासनिक सुलक ₹0 200.00 + जीएसटी</li> <li>● प्रोसेसिंग फीस 0.50 प्रतिशत (न्यूनतम ₹0 4000.00) +जीएसटी सहित ऋणियों से ली जायेगी। तथा उक्त प्रोसेसिंग फीस में सी0ए0 द्वारा ली जाने वाली फीस भी सम्मिलित होगी। सी0ए0 द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>₹0 10,00,000.00 तक ऋण</td><td>₹0 4000.00</td></tr> <tr> <td>₹0 10,00,001.00 से ₹0 25,00,000.00 तक ऋण</td><td>₹0 6000.00</td></tr> <tr> <td>₹0 25,00,001.00 से ₹0 60,00,000.00 तक ऋण</td><td>₹0 7500.00</td></tr> </table> <p>Appraisal from CA should be done only for proposals which satisfy applicable condition as stipulated in Bank's MSME Policy and circular.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● उक्त दरों में सी0ए0 द्वारा फाइनेन्शियल एवं टैक्निकल एप्रेजल, एमएसएमई ड्यू डेलीजेन्स एवं आईटीआर वेरीफिकेशन आदि किया जायेगा।</li> <li>● उद्यमियों एवं उनकी फर्म/यूनिट को तथा गारण्टर्स को बैंक का नाम मात्रिक सदस्य अवश्य बनाया जायेगा।</li> <li>● अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त रिपोर्टों हेतु अधिवक्ता</li> </ul>	₹0 10,00,000.00 तक ऋण	₹0 4000.00	₹0 10,00,001.00 से ₹0 25,00,000.00 तक ऋण	₹0 6000.00	₹0 25,00,001.00 से ₹0 60,00,000.00 तक ऋण	₹0 7500.00
₹0 10,00,000.00 तक ऋण	₹0 4000.00						
₹0 10,00,001.00 से ₹0 25,00,000.00 तक ऋण	₹0 6000.00						
₹0 25,00,001.00 से ₹0 60,00,000.00 तक ऋण	₹0 7500.00						



	<p>द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस अधिकतम रू0 2000.00 होगी, यह प्रोसेसिंग फीस से पृथक होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्टॉक/परिसम्पत्तियों आदि का वैल्यूवेशन कराने के लिए वैल्यूवेशन फीस तथा स्टॉक का आडिट करने या अन्य कोई आडिट करने जैसा बैंक उचित समझे के सम्बन्ध में जो फीस आडिटर द्वारा चार्ज की जायेगी उसे ऋणी द्वारा वहन किया जायेगा।</li> </ul> <p>सीजीटीएमएसई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गारण्टी फीस ऋणी से ली जायेगी।</p>
13. खाते में लेनदेन/राशि का वितरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>इन्ट्रस्ट सब्वेंशन एवं क्रेडिट गारण्टी सपोर्ट पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से होगा।</li> <li>बैंक द्वारा इस योजनान्तर्गत ऋणियों/लाभार्थियों के आधार से लिंक खाते में फण्ड का अन्तरण किया जायेगा। इस हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा कि लाभार्थी का खाता आधार से लिंक होना चाहिए।</li> </ul>
14. ब्याज सबवेंशन (ब्याज प्रतिपूर्ति अनुदान)	<ul style="list-style-type: none"> <li>रू0 60.00 लाख तक के ऋणों पर भारत सरकार की ओर से 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता (Interest Subvention) प्रदान की जानी है। Interest Subvention प्राप्त होने पर ऋणी के खाते को क्रेडिट किया जायेगा। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी मैचिंग उपादान प्रदान की जायेगी (उपादान हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें लागू होंगी यथा-किसान एग्री इण्टरप्रन्योर को रू0 50.00 लाख तक की ऋण राशि पर राज्य सरकार Interest Subvention देती है आदि)।</li> <li>यह सबवेंशन अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।</li> <li>सबवेंशन की अनुमति केवल तब तक दी जाएगी जब तक कि खाता मानक (Standard Assets) श्रेणी के अंतर्गत हो। इसके अलावा, यदि खाता एन0पी0ए0 में चला जाता है, तो खाते के एन0पी0ए0 श्रेणी के अंतर्गत रहने की अवधि के दौरान कोई सबवेंशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाते को मानक श्रेणी में अपग्रेड करने की तारीख से सबवेंशन की अनुमति दी जाएगी। एक बार</li> </ul>

	<p>खाते को मानक श्रेणी में अपग्रेड करने के बाद वह उस अवधि के लिए सबवेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश लागू होंगे। बैंक अपनी तरफ से कोई ब्याज अनुदान नहीं देगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऋणी को ब्याज सबवेंशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं जारी होने पर ही दिया जा सकेगा।</li> <li>• ब्याज सबवेंशन पहले संवितरण की तारीख से दिया जाएगा और अगले साल से यह बकाया ऋण के लिए 1 अप्रैल से 7 साल तक हर साल लागू होगा या भारत सरकार/राज्य सरकार की गार्ड लाइन्स के अनुसार होगा।</li> </ul>
15. योजना का मेल मिलाप (Dovetailing /convergence of the Scheme)	<p>केन्द्र/राज्य सरकार की कोई भी योजना जिसके नियम एवं शर्तों के अधीन यदि लाभार्थी को लाभ पहुंचाने हेतु मेल-मिलाप (Dovetailing) किया जा सकता है तथा सभी लाभ लाभार्थी सम्बन्धित विभाग को आवेदन कर प्राप्त कर सकता है। लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का लाभार्थी द्वारा पालन किया जायेगा।</p>
16. प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट एवं हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट	<p>An online platform will be made available in collaboration with participating lending institutions to provide information and loan sanctioning facility. Agri Infra fund will be managed and monitored through an online MIS platform. It will enable all the qualified entities to apply for loan under the fund.</p>
17. योजना का प्रक्रिया प्रवाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करेगा जिसके बाद उसे पंजीकरण क्रेडेंशियल प्राप्त होंगे।</li> </ul> <p>(All assets created under this financing facility shall be geo tagged. The District Monitoring Committee and respective lending entity shall ensure that updated information on such geo tagged assets is available on the online portal)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी पोर्टल पर उपलब्ध एक आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आवेदन के साथ आवेदक द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) और संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।</li> <li>• इस आवेदन को मंत्रालय में केन्द्रीय पी0एम0यू0 द्वारा सत्यापित किया जाएगा और फिर पोर्टल पर आवेदक द्वारा चुने गए ऋणदाता संस्थान को अग्रेषित किया जाएगा।</li> <li>• ऋण देने वाला संस्थान परियोजना का मूल्यांकन करेगा और वह तय करेगा कि ऋण मंजूर किया जाए या परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए।</li> <li>• ऋणदाता बैंक द्वारा लाभार्थी को ऋण के वितरण के बाद, ऋण देने वाले बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर भारत सरकार द्वारा बैंक को ब्याज सबवेंशन जारी किया जाएगा।</li> <li>• Interest subvention and credit guarantee support will be released to Banks and lending institutions through PFMS, Disbursal of funds by lending entities to beneficiaries under this scheme shall be in Aadhar linked bank account.</li> </ul>
18. सुरक्षा दस्तावेज	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. मांग और वचन पत्र,</li> <li>2. सृजित सम्पत्तियों का दृष्टि बंधक पत्र</li> <li>3. सामान्य अवधि ऋण समझौता</li> <li>4. निरंतरता का पत्र</li> <li>5. सामान्य ग्रहणाधिकार और सेटऑफ का पत्र</li> <li>6. सिबिल स्कोर/सीएमआर/एनटीसी/फिट रैंक ली जायेगी।</li> <li>7. थर्ड पार्टी गारंटी या मालिकों/भागीदारों/प्रवर्तकों/ निदेशकों आदि की व्यक्तिगत गारंटी।</li> <li>8. अचल संपत्ति भूमि और भवनों का बंधक रखने हेतु निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर लिये जायेंगे।</li> <li>9. प्लान्ट, मशीनरी, स्टॉक को प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रखा जायेगा तथा हाइपोथिकेट किया जायेगा, इस वित्त पोषण सुविधा से सृजित की जाने वाले ऐसेट को जियो टैग किया जायेगा।</li> <li>10. मंजूरी में निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज जैसे कृषि भूमि का अकृषि संपरिवर्तन, सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों से</li> </ol>



	आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) क्लीयरेंस सर्टीफिकेट, आदि ।
19. दस्तावेज की आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केवाईसी दस्तावेज (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)</li> <li>• पासपोर्ट साइज फोटो</li> <li>• भू अभिलेख</li> <li>• कोटेशन/चालान</li> <li>• परियोजना रिपोर्ट</li> <li>• आईटी रिटर्न</li> <li>• पंजीकरण आदि अन्य दस्तावेज जो बैंक द्वारा परिपत्र के माध्यम से मांगे गये हों।</li> <li>• केवाईसी0 डॉक्यूमेंट्स</li> <li>• ऋणी, ऋण लेने वाली फर्म एवं उसके गारण्टर को बैंक का नामात्रिक सदस्य बनाया जायेगा।</li> <li>• प्रोजेक्ट रिपोर्ट का ड्यू डेलीजेन्स तथा उसके वित्तीय पहलुओं का अप्रिजल सीए के माध्यम से कराया जायेगा तथा सीए की रिपोर्ट के आधार पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा अथवा नहीं।</li> <li>• ऋण स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के मामले में सीए अपना स्पष्ट मन्तव्य देगा।</li> <li>• सीए की फीस एमएसएमई परिपत्र में निर्गत व्यवस्थानुरूप होगी।</li> <li>• प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेन्स शीट सी.ए. से बैंक शाखायें सत्यापित करायेंगी तथा उनसे ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में स्पष्ट मन्तव्य प्राप्त करेंगी।</li> <li>• वन्धक की जाने वाली भूमि, भवन के सम्बन्ध में नॉन इन्कम्प्लेन्स सर्टीफिकेट, लीगल रिपोर्ट आदि अधिवक्ता के माध्यम से ली जायेगी तथा अधिवक्ता की फीस ऋणी द्वारा वहन की जायेगी।</li> </ul>
20. वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं पर विचार करने के लिए वित्तीय मूल्यांकन मानदंड	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. लाभ लागत अनुपात (बीसीआर) -1 या अधिक</li> <li>2. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)- 0 या अधिक</li> <li>3. रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर)- न्यूनतम 15%</li> <li>4. ऋण सेवा कवरेज अनुपात(डीएससीआर)-न्यूनतम 1.5%</li> </ol>



21. ऋण स्वीकृति	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्राप्त ऋण आवेदन पत्र विधिक रूप से पूर्ण कराने के पश्चात् शाखा के अधिकारी द्वारा प्रस्तावित परियोजना साइट की स्वीकृति पूर्व विजिट की जाएगी तथा बैंक अधिकारी स्वीकृति पूर्व विजिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऋण आवेदन पत्र एवं ऋण सम्बन्धी अन्य प्रपत्रों की स्कूटिनी शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी द्वारा की जाएगी तथा समस्त पहलुओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ऋण कमेटी ऋण को स्वीकृत करेगी एवं ऋण शाखा स्तर पर ही स्वीकृत किया जायेगा। ऋण स्वीकृति हेतु मुख्यालय नहीं भेजा जायेगा।</li> <li>2. ऋण मूल्यांकन के आधार पर ऋण समिति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।</li> <li>3. ऋण समिति द्वारा स्वीकृति के उपरांत बैंक शाखा द्वारा आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। स्वीकृति पत्र में ऋण समिति द्वारा स्वीकृति के साथ निर्धारित सभी पूर्ति एवं दशाएं भी निर्देशित की जाएगी।</li> <li>4. लाभार्थी द्वारा स्वीकृति की सभी शर्तें एवं नियम लिखित रूप में मंजूर करने के पश्चात सभी आवश्यक सिक्योरिटी दस्तावेज/ कागजात बैंक की शाखा प्राप्त करेगी। बैंक शाखा स्वीकृत ऋण राशि वितरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि लाभार्थी से सभी दस्तावेज/कागजात प्राप्त कर लिये गए हैं, तदोपरान्त ऋण को डिस्बर्स किया जायेगा।</li> </ol>
22. योजना का कार्यक्षेत्र एवं योजना को लागू करना।	इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 की समस्त शाखायें उ0प्र0 की सीमा के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत कर सकेंगे।
23. सरसई रजिस्ट्रेशन	ऋण के लिए जो भी अचल सम्पत्ति मॉडगेज/इक्विटेबल मॉडगेज की जाएगी उसका पंजीयन "सरसई पोर्टल" में करना अनिवार्य है तथा सरसई रिपोर्ट डाउनलोड भी करनी होगी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बन्धक रखे जाने वाली भूमि या भवन पूर्व से बन्धक नहीं है एवं अपलोड किये जाने का भी प्रमाण पत्र पत्रावली में सुरक्षित रखें।
24. अन्य नियम और शर्तें	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना के तहत उपलब्ध किसी भी अनुदान या सब्सिडी का लाभ इस वित्त पोषण सुविधा के तहत परियोजनाओं के लिए लिया जा सकता है। पूंजी सब्सिडी के मामलों में, ऐसी राशि को प्रवर्तक के योगदान के रूप में माना जाएगा। हालांकि, प्रमोटर के योगदान के रूप में</li> </ol>

	<p>परियोजना लागत का न्यूनतम 20% अनिवार्य होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>योजना वर्तमान में 2032-33 तक लागू रहेगी। अतः यदि कोई ऋण 2025-26 में स्वीकृत किया जाता है तो मोराटोरियम अवधि सहित 07 वर्ष के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु यदि ऋण 2026-27 में स्वीकृत किया जा रहा है तो मोराटोरियम अवधि सहित 06 वर्ष हेतु ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु यदि ऋण 2030-31 में स्वीकृत किया जा रहा है तो ऋणी को 06 माह की मोराटोरियम अवधि ही प्रदान की जा सकेगी तथा 02 वर्ष के अन्तर्गत अर्थात् 2033 से पूर्व ऋण वसूल हो जाना चाहिए।</li> <li>भारत की DAC&amp;FW सरकार योजना में संशोधन/संशोधन/वापस लेने/समाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी और/या योजना दिशानिर्देशों में संशोधन/संशोधन करना।</li> <li>बैंक जोखिम मूल्यांकन में सतर्कता पूर्वक करेगा और ऋण पात्रता के आकलन और उधारकर्ता / लाभार्थी की चुकौती क्षमता सहित परिश्रमी मूल्यांकन और मंजूरी प्रक्रियाओं को अपनाएगा।</li> <li>बैंक समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों /संशोधनों सहित योजना दिशा निर्देशों के तहत, DAC&amp;FW (G01) RBI/ NABARD द्वारा जारी सभी मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करेगा। बैंक त्रैमासिक आधार पर डीएसी एंड एफडब्ल्यू (जी 01) को उपयोग/अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और योजना के तहत वित्तपोषित बुनियादी ढांचा इकाई के पूरा होने तक निर्माण की भौतिक प्रगति के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। शाखा/बैंक प्रस्तावित इकाई के पूर्ण होने पर निर्माण पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऋण राशि की किस्त/किस्त के संवितरण की तिथि से अधिकतम 12 महीने के भीतर एक समेकित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।</li> <li>बैंक प्रत्येक उधारकर्ता/लाभार्थी को एक विवरण प्रदान करेगा, जो उसे सबवेंशन के रूप में दी गई राशि, सबवेंशन को कैसे समायोजित किया गया है और उसके पुनर्भुगतान दायित्वों / समान मासिक किस्तों (ईएमआई)</li> </ol>
--	---

	<p>पर सब्सिडी के प्रभाव को समझने में मदद करेगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. बैंक DAC&amp;FW द्वारा समय-समय पर आवश्यक सभी जानकारी, और विवरण प्रदान करेगा।</li> <li>8. ऋणी द्वारा जिस फर्म का कोटेशन लिया जायेगा, उसका भलीभांति परीक्षण करने के उपरान्त ही फण्ड डिस्बर्स किया जायेगा साथ ही फर्म का पैन नम्बर, आधार नम्बर, जीएसटीएन नम्बर आदि होना आवश्यक है।</li> <li>9. ऋण का अप्रेजल शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं प्रतिमाह के 10 तारीख तक स्टॉक का स्टेटमेंट अवश्य प्राप्त किया जायेगा।</li> <li>10. किराये के भवन का, जहां पर यूनिट स्थापित है, उसका ऋण एग्रीमेंट कराया जाना आवश्यक है।</li> </ol>
--	--

नोट:- एससी/एसटी एवं महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों हेतु ऋण शर्तों का पालन बैंक द्वारा किया जायेगा, जैसा कि एआईएफ योजना गाईड लाईन में है।

अग्रेतर Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare Ministry of Agriculture DAC & FW (GOI) Government of India, New Delhi की स्कीम से सम्बन्धित गाईड लाईन्स एवं चेक लिस्ट इस निर्देश के साथ संलग्न है कि उक्त गाईड लाईन्स का भलीभांति अध्ययन करते हुए शाखा स्तर पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा-निर्देश परिपत्र निर्गत होने के तिथि से प्रभावी होंगे।

संलग्नक: यथोक्त

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. श्री राहुल श्रीवास्तव, प्रबन्धक, आईटी सेल को इस निर्देश के साथ कि वे बैंक की वेबसाईट पर एआईएफ परिपत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक



**Scheme Guidelines  
for  
CENTRAL SECTOR SCHEME  
of  
Financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'**



**Revised Scheme Guidelines**

**September 2024**

**Department of Agriculture & Farmers Welfare  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
Government of India**



### Index

S. No	Particulars	Page No.
1	Introduction	3
2	Rationale of the Scheme	3-4
3	Objectives of Scheme	4-5
4	Implementation Period of Scheme	5
5.	Government Budgetary Support	6
6.	Eligible Projects	7-10
7.	Size of the financing facility& eligible beneficiaries	10
8.	Number of Projects per entity eligible under the scheme	11
9.	Participating institutions	11
10.	Refinance	11
11	Cap on lending rate	11-12
12.	Project Management and handholding support	12
13.	Convergence	12
14	Revisit of the Scheme	12
15	Monitoring framework	13
16	Output and outcome monitoring framework (OOMF)	13
17	Linkage with PFMS	13
18	Criteria for selection of eligible borrower	13
19	VGF requirement	13
20	Sector specific focus	14
21	States specific focus	14

# **Scheme Guidelines for CENTRAL SECTOR SCHEME of financing facility under 'Agriculture Infrastructure Fund'**

## **1 Introduction**

The role of infrastructure is crucial for agriculture development and for taking the production dynamics to the next level. It is only through the development of infrastructure, especially at the post-harvest stage that the produce can be optimally utilized with opportunity for value addition and fair deal for the farmers. Development of such infrastructure shall also address the vagaries of nature, the regional disparities, development of human resource and realization of full potential of our limited land resource.

In view of above, the Hon'ble Finance Minister announced on 15.05.2020, ₹1 lakh crore Agri Infrastructure Fund for farm-gate infrastructure for farmers. Financing facility of ₹ 1,00,000 crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc. Impetus for development of farm-gate & aggregation point, affordable and financially viable Post Harvest Management infrastructure.

Accordingly, DA&FW has formulated the Central Sector Scheme to mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects relating to post-harvest management Infrastructure and viable farming assets through incentives and financial support.

Subsequently, in the budget announcement made on 01.02.2021, it was decided to extend the benefit of the scheme to APMCs. Accordingly, modifications in the scheme were carried out with the approval of Cabinet to make it more inclusive.

## **2 Rationale of the Scheme**

Agriculture and allied activities are the primary income source for ~58% of total population of India. ~85% of the farmers are Small Holding Farmers (SHFs) with less than 2 hectares of land under cultivation and manage ~45% of agricultural land. Annual income of



majority of the farmers is very low. Further, India has limited infrastructure connecting farmers to markets and hence, 15-20% of yield is wasted which is relatively high in comparison to other countries where it ranges between 5-15%. Investment in agriculture in India has further been stagnant with less than 2% CAGR over last 5 years. Investment in FY17 was ~ ₹ 2.19 lakh crore out of which private sector share was ~83% vs. a higher investment of ~ ₹ 2.50 lakh crore in FY14 and a higher share of private sector at ~68%. Also, lack of investor confidence is leading to lower plowback ratio (~14% of Gross Value addition in FY18) vs. other sectors (~33% of Gross Value addition in FY18).

### 3 Objectives of the Scheme

To mobilize a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and viable farming assets through incentives and financial support in order to improve agriculture infrastructure in the country. This financing facility will fulfil numerous objectives for all the stakeholders in the agriculture eco-system.

a. Farmers (including FPOs, PACS, Marketing Cooperative Societies, Multipurpose cooperative societies, State Agencies, Agricultural Produce Market Committees (Mandis), National & State Federations of Cooperatives, Federations of FPOs and Federations of Self Help Groups (SHGs) etc.).

- Improved marketing infrastructure to allow farmers to sell directly to a larger base of consumers and hence, increase value realization for the farmers. This will improve the overall income of farmers.
- With investments in logistics infrastructure, farmers will be able to sell in the market with reduced post-harvest losses and a smaller number of intermediaries. This further will make farmers independent through improved access to market.
- With modern packaging and cold storage system access, farmers will be able to further decide when to sell in the market and improve realization.
- Viable farming assets for improved productivity and optimization of inputs will result in substantial savings to farmers.

b. Government

- Government will be able to direct priority sector lending in the currently unviable projects by supporting through interest subvention, incentive through convergence and credit guarantee. This will initiate the cycle of innovation and

private sector investment in agriculture.

- Due to improvements in post-harvest infrastructure, government will further be able to reduce national food wastage percentage thereby enable agriculture sector to become competitive with current global levels.
- Central/State Government Agencies or local bodies will be able to structure viable projects on their own or PPP projects for attracting investment in agriculture infrastructure.

c. Agri-entrepreneurs and startups

- With a dedicated source of funding, entrepreneurs will push for innovation in agriculture sector by leveraging new age technologies including IoT, AI, etc.
- It will also connect the players in ecosystem and hence, improve avenues for collaboration between entrepreneurs and farmers.

d. Banking ecosystem

- With Credit Guarantee, convergence and interest subvention lending institutions will be able to lend with a lower risk. This scheme will help to enlarge their customer base and diversification of portfolio.
- Refinance facility will enable larger role for cooperative banks and RRBs.

e. Consumers

- With reduced inefficiencies in post-harvest ecosystem, key benefit for consumers will be a larger share of produce reaching the market and hence, better quality and prices. Overall, the investment via the financing facility in agriculture infrastructure will benefit all the stakeholders in the eco-system.

#### **4 Implementation Period of Scheme**

The Scheme will be operational from 2020-21 to 2032-33. Loan disbursement under the scheme will complete in six years, i.e. by the end of Financial Year 2025-26. As on 30<sup>th</sup> June 2024, ₹43,391 crores have been sanctioned, out of which ₹28,171 crores have been disbursed under the scheme. Remaining ₹71,829 crores out of ₹1 lakh crores will be disbursed during the remaining period between 2024-25 and 2025-26. Repayment period covered under the financing facility will be for a maximum period of 7 years including the moratorium period of up to 2 years.



## 5 Government Budgetary Support

Budgetary support will be provided for interest subvention and credit guarantee fee as also administrative cost of PMU. The details are as below:-

Sl.No.	Name of Component	Norms
1	Interest Subvention Cost	All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹ 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond ₹ 2 crore, then interest subvention will be limited up to ₹ 2 crore.
2	Credit Guarantee Cost	Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to ₹ 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DA&FW and NABSanrakshan Trustee Company Pvt. Ltd. However, FPOs are also eligible for reimbursement of credit guarantee fee under AIF.
3	Administration Cost of PMU	Farmers Welfare Programme Implementation Society under DA&FW will provide PMU support to the scheme at the central level. With the financial assistance from DA&FW, each of the States/ UTs will set-up PMUs in their respective states for creation of awareness, identifying potential clusters, mobilization of applications, review of all the stakeholders, and providing all necessary

## 6 Eligible Projects

The scheme will facilitate setting up and modernization of key elements of the value chain including

### A. Post-Harvest Management Projects

- Supply chain services including e-marketing platforms
- Warehouse & Silos
- Cold Stores and Cold Chain
- Packaging Units
- Assaying Units
- Sorting and grading units
- Logistic Facilities- Reefer Van & Insulated vehicles
- Ripening Chambers
- Farm residue/waste management infrastructures
- Primary Processing activities\* (*See table 1*)
- Integrated primary and secondary processing activities\*\* (*See table 1*)

### B. Viable Farming Assets

- Organic inputs production – Vermicomposting etc.
- Compressed Biogas ( CBG) Plant
- Bio stimulant production units
- Infrastructure for smart and precision agriculture -Purchase of drones, boom sprayer, putting up specialized sensors on field, Blockchain and AI in agriculture etc. ,Remote sensing and Internet of Things (IOT) such as automatic weather station, Farm advisory services through GIS applications.
- Nursery
- Tissue culture
- Seed Processing
- Custom Hiring Center –farm machinery/ implements ( *minimum of 4 in quantity*)
- Farm/Harvest Automation (*combine harvester, sugarcane harvester etc.*)
- Setting up of Decentralized Ground/ Stilt Mounted Grid Connected Solar based Power Plants (PM-KUSUM component A)
- Standalone solar pumping system (PM-KUSUM component B)
- Solarization of grid connected agri-pump under PM-KUSUM component C
- Integrated Spirulina production & processing units
- Sericulture processing unit
- Honey processing
- Plant quarantine units
- Projects identified for providing supply chain infrastructure for clusters of crops including export clusters.
- Projects promoted by Central/State/Local Governments or their agencies under PPP for building viable farming assets or post-harvest management projects.
- Hydroponic Farming
- Mushroom farming



- Vertical farming
- Aeroponic farming
- Poly house/ Greenhouse
- Logistics facilities (including non-refrigerated/insulated vehicles)#
- Tractor#

Note 1: Solarization of any of the eligible infrastructure can also be financed under AIF.

Note 2: Digital Connectivity and optic fiber infrastructure shall be eligible investment as part of development of the aforementioned eligible projects.

\*\*Note 3: Standalone secondary processing infrastructures are not eligible.

#Note 4: Not eligible for individuals/ farmers

Note 5: Component-A of PM-KUSUM eligible for Individual farmers/ Group of farmers/ FPOs/ Cooperatives/ Panchayats to set up solar power plants of capacity up to 2 MW on barren/cultivable/uncultivable/pasturelands or marshy lands.

**Table 1 Crop wise Eligible Activities**

Sl. No.	Crops	Eligible Primary Processing Activities*	Eligible Integrated Secondary Processing Activities**	Ineligible activities
1	Cereals & Millets <i>Wheat, Rice, Sorghum, Barley, Maize, Oat, Etc.</i>	Cleaning, De-Stoning, Sorting & Grading, Hulling, Milling (Flour, Maida, Sooji, Daliya), Pounding, Grinding, Tempering, Parboiling, Soaking, Drying, Sieving, Irradiation, Packaging, Flaking, Storage (Warehouse, Silos)	Products like Bread, Biscuits, Pasta, snack foods etc., starch, Oat Meal, Sorghum Syrup, vinegar, Roasted, Fortified, Puffed products, animal feed	Malting and alcoholic beverage making
2	Fruits And Vegetables	Washing, Cleaning, Drying, Sorting, Grading, Freezing (IQF & Blast), Blanching For Primary Processing, Cooling, Waxing, Conditioning, Pack house, Cold Store, Ripening Chamber, Reefer Van, Bucket Elevators, Packaging	fruit juices, pulp, ketchup, fruit concentrates, Jams, jellies, Candies, marmalades, fruit fillings, and canned fruits. Canned vegetables, vegetable juices, pickles, chutneys, and vegetable purees., vinegar, dehydrated fruit and vegetables, Fruit and Vegetable Powders & flour	Alcoholic beverage making
3	Oilseeds & Oil Palms <i>Groundnut, Rapeseed &amp; Mustard, Soybean, Sunflower, Sesame, Safflower, Linseed, Olives, Oil Palm Etc.</i>	Cleaning, De-Stoning, De-Husking, (Decorticating Machines), Winnowing, Oil Extraction (Ghani, Hydraulic Press etc.), Solvent Extraction, Oil Seed Cake	Refining	Oil-based lubricants, Biodiesel
	Pulses	Cleaning, De-Stoning, Drying,	Pulse-based snacks (roasted	Pulse-based

Sl. No.	Crops	Eligible Primary Processing Activities*	Eligible Integrated Secondary Processing Activities**	Ineligible activities
4	Bengal Gram, Pigeon Peas, Green Gram, Chick Peas, Black Gram, Red Kidney Beans, Black Eyed Peas, White Peas Etc.	Sorting & Grading, De-Husking, Splitting, De-Hulling, Milling (Besan), Irradiation, Packaging, Storage	chickpeas, lentil chips, and pea crisps), Canned pulses, guar gum, Pulse-based flake, animal feed, ready to cook & ready to eat foods, Papads etc.	protein powders
5	Spices Red Chilli, Cumin, Clove, Coriander, Cinnamon, Garlic, Ginger, Turmeric, Fenugreek, Cardamom Etc.	Cleaning, Drying, Sorting, Boiling, Polishing, Grinding, Packaging, Storage, Irradiation	Spice pastes, Spices mix, extracts and essential oils, Infused oils and vinegars, Pickled spices	
6	<b>Cash Crops</b>			
	Cotton	Cleaning, Drying, Ginning, Pressing & Bailing, Linting, Cotton Seed Oil, Seed Cake	Fibre Making, Fibre scouring	Weaving, Textiles, plastics, synthetic rubber,
	Sugarcane	Cane Unloading, Cleaning, Cane Breaking, Cane Milling, Straining, Evaporators, Centrifugation, Storage Tanks, Dryers, Sugar Crystals, Jaggery, Packaging & Storage		Making Paper & Board with Bagasse, Fermentation, Alcoholic Distillation
	Jute	Cutting, Retting, Stripping, Washing, Drying, Bailing, Packing, Storage	Jute rope making	Making Jute Cloth, Bags, Sacks
	Tea & Coffee & Cocoa	Cleaning & Washing, Withering, Rolling, Fermentation, Drying, Sorting, Drying Of Cherries, Hulling, Pulping, Oxidation, Packaging (Including Tea Bags), White Tea, Green Tea, Black Tea	Cocoa butter, Cocoa bar, Instant/ beaten coffee	Cosmetic products such as scrub, body wash etc.
	Coconut	Dehusking, Deshelling, Cutting, Drying (Copra), Grinding, Extraction Of Coconut Water, Coconut Milk Extraction, Centrifugation, Hot Processing, Virgin Coconut Oil, Packaging	Butter, coir rope making	Cream
	Rubber	Mastication, Mixing, Shaping, Curing, Irradiation		Products like Tyres, Mattresses, Bottles, Boots etc.
	Tobacco	Cleaning, Grading, Sorting, Curing, Drying, Storage		Making of Chew, Cigars, Dips Etc.
7	Nuts Cashew, Almonds, Walnuts, Pistachios etc	Cleaning, Grading, Streaming In Boiler, Shell Cutting, Drying, Peeling, Grading, Packaging, Shelling, Separation,	Nut butter, roasted nuts, nut milk, nut flour, candied nuts, and nut oils and snacks.	



Sl. No.	Crops	Eligible Primary Processing Activities*	Eligible Integrated Secondary Processing Activities**	Ineligible activities
		Packaging, Hulling, Washing, Drying, Storage, Packaging, Conveying Belts		
8	Herbal, Medicinal & Aromatic Crops <i>Barberry, Liquorice, Bael, Isabgol, Guggal, Kerth, Aonla, Chandan, Senna, Baiberang, Brahmi, Eucalyptus, Jatamansi Etc.</i>	Cleaning, Sorting, Drying, Milling, Extraction Of Oil, Packaging, Storage	Syrup	Herbal supplements like capsules, tablets, or other forms, Pills, Cream,
9	Bamboo	Drying, Cutting, Stripping, Formation Of Sheets, Bamboo Charcoal, Powder, Granules, Bamboo Treatment Plant, Bamboo Depots & Godown	Processed Food Products like Pickles, ready to eat Etc., Products such as Fibre, etc.	Furniture, Bamboo textiles, agarbatti
10	Fodder Crops <i>Berseem, Forage Sorghum, Etc.</i>	Cutting, Mixing, Grinding	Feed blocks, Fodder meals, Hay cubes and pellets	Protein concentrates
11	Tuber Crops <i>Sweet Potatoes, Cassava Etc.</i>	Peeling And Washing, Grating, Fermentation, Drying, Sieving, Milling, Storage	Chips, flour, Starch	Alcoholic Products
12	Arecanut	Cleaning, Dehusking, Peeling, Splitting, Boiling, Drying, Packaging		Hardboard, Insulation Wool, Cushions, Paper, Paper Board etc.

*Note: The above list is illustrative only and not exhaustive.*

## 7 Size of the financing facility and eligible beneficiaries

₹ 1 Lakh Crore to be provided by banks and financial institutions as loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Marketing Cooperative Societies, Farmer Producers Organizations (FPOs), Self Help Group (SHG), Farmers, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups and Central/State agency or Local Body sponsored Public Private Partnership Projects, State Agencies, Agricultural Produce Market Committees (Mandis), National & State Federations of Cooperatives,

Federations of FPOs (Farmer Produce Organizations) and Federations of Self Help Groups (SHGs). APMCs operating regulated markets for agriculture and allied sector produce including fisheries shall also be eligible.

PACS who have adopted digitization for handling its operations will be given preference under this scheme.

## **8 Number of Projects per entity eligible under the scheme**

Interest subvention for a loan upto ₹2 crore in one location is eligible under the scheme. Multiple projects in one location are also eligible with an overall cap of ₹2 crore. In case, one eligible entity puts up projects in different locations then all such projects will be eligible under the scheme for loan upto ₹2 crore. However, for a private sector entity, such as farmer, agri entrepreneur, start-up there will be a limit of maximum of 25 such projects. This limitation of 25 projects will not be applicable to state agencies, cooperatives, national and state federations of cooperatives, FPOs, federations of FPOs, SHGs and federation of SHGs. Location will mean physical boundary of a village or town having a distinct LGD (Local Government Directory) code. Each of such projects should be in a location having a separate LGD (Local Government Directory) Code.

For APMCs, multiple projects of different infrastructure types can be sanctioned in its designated market area. In such cases, interest subvention for a loan upto ₹ 2 Crore will be provided for each project of different infrastructure types e.g. cold storage, sorting, grading and assaying units, silos, etc. within the designated market area of the APMC.

## **9 Participating institutions**

All scheduled commercial banks scheduled cooperative banks, Regional Rural Banks (RRBs), Small Finance Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and National Cooperative Development Corporation (NCDC) may participate to provide this financing facility, after signing of Memorandum of Understanding (MoU) with National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD)/DA&FW.



## **10 Refinance**

If required, need based refinance support will be made available by NABARD to all eligible lending entities including cooperative banks and RRBs as per its policy.

## **11 Cap on lending rate**

Lending rate of participating lending entities will be decided after due consultation with lending entities and same will be circulated to all stake holders. Lending institutions will sign MOU with DA&FW/ NABARD for implementation of the Scheme. MOUs to be signed by DA&FW/NABARD with banks/financial institutions with a view that DA&FW/NABARD will negotiate cap on lending rates in a fair manner.

## **12 Project Management and handholding support**

An online platform will be made available in collaboration with participating lending institutions to provide information and loan sanctioning facility. Agri Infra fund will be managed and monitored through an online MIS platform. It will enable all the qualified entities to apply for loan under the fund. The system will also provide benefits such as transparency of interest rates offered by multiple banks, scheme details including interest subvention and credit guarantee offered, minimum documentation, faster approval process as also integration with other scheme benefits. At the back end, the platform will also provide multiple views of dashboards across district; state and national level PMUs to monitor the total sanctioned amount and number of borrowers, total interest subvention benefit availed, loan statement summary, demographic and geographic mix of borrowers and type of projects.

Each of the States/ UTs will set-up PMUs in their respective states for creation of awareness, identifying potential clusters, mobilization of applications, review of all the stakeholders, and providing all necessary handholding support under the scheme.

Project reports with indicative unit costs will be prepared by Central and State PMUs for guidance of beneficiaries and lending entities. Such project reports shall be available on online platform.

## **13 Convergence**

Any grant or subsidy available under any present or future scheme of Central/State government can be availed for projects under this financing facility, e.g. MIDH, PMFME,



SMAM, Gobar-Dhan, PMKSY, AMI, PACS as MSC, RKVY, PM-KUSUM (A, B and C), PMEGP etc. In cases of capital subsidy such amount shall be considered as promoter's contribution. However, a minimum of 10% of the project cost shall be mandatory as promoter's contribution.

#### **14 Monitoring framework**

The National, State and District Level Monitoring Committees to ensure real-time monitoring and effective feed-back about the implementation of the proposed scheme. The Committees will be set up as per **Annexure-A**.

All assets created under this financing facility shall be geo tagged. The District Monitoring Committee and respective lending entity shall ensure that updated information on such geo tagged assets is available on the online portal.

#### **15 Output And Outcome Monitoring Framework (OOMF)**

The Output and Outcome Monitoring Framework (OOMF) will be a part of monitoring system and the measurement of outcome indicators will be monitored periodically by DLMC, SLMC and NLMC.

#### **16 Linkage with PFMS**

Interest subvention and credit guarantee support will be released to Banks and lending institutions through PFMS.

Disbursal of funds by lending entities to beneficiaries under this scheme shall be in Aadhaar linked bank account.

#### **17 Criteria for selection of Eligible Borrower**

Lending institutions will decide criteria for selection of eligible borrower in consultation with NABARD and monitoring committees, PMUs and keeping in mind the viability of the projects and to avoid NPA.

#### **18 VGF Requirement**

In case VGF requirement is projected by central / state / local bodies, norms as

prescribed by DEA for PPP projects will be adhered to.

### **19 Sector specific focus**

24% of total grants – in – aid under the scheme should be utilized for SC/ST entrepreneurs (16% for SC and 8% for ST). Besides this, lending institutions would ensure adequate coverage of entrepreneurs belonging to women and other weaker segments of society may be provided loan on priority basis to ensure that benefits of implementation are inclusive and accrued to the intended beneficiaries in accordance with Government guidelines and policies.

### **20 State specific focus**

Tentative State wise allocation of financing facility has been worked out on the basis of the ratio of total value of output of Agriculture and Allied sectors of States/UTs and placed at **Annexure- B**

**Annexure-A**  
**Monitoring framework**

**(i) National level Monitoring Committee (NLMC)**

**Composition :-**

Following will be the Members and Chairman of the NLMC:-

- a. Secretary (DA&FW) (Chairman)
- b. MD SFAC
- c. MD, NCDC
- d. Special Secretary/Additional Secretary and FA (DA&FW)
- e. Additional Secretary DFS
- f. Additional Secretary (DA&FW, GoI)
- g. Chairman, NABARD or his representative
- h. Principal Secretary-State Government (s)- Four States by rotation
- i. State Nodal Officers of four States (by rotation)
- j. Joint Secretary (DA&FW) and CEO of Farmers Welfare Programme Implementation Society Member Secretary

**Functions:-**

1. National level Monitoring Committee (NLMC) will guide and steer the implementation of the scheme. It will approve the guidelines for implementation of the scheme.
2. National level Implementation Committee (NLIC) will examine and recommend the guidelines for implementation of the scheme. It also will ensure and review the implementation of the scheme as per approved guidelines by the National level Monitoring Committee (NLMC)

**(ii) State level Monitoring Committee Composition:-**

Following will be Members and Chairman of the SLMC :-

- a. Chief Secretary –Chairman
- b. Agriculture Production Commissioner/Principal Secretary Agriculture
- c. Principal Secretary (Cooperation)
- d. Registrar of Cooperative Societies (RCS)
- e. Chief General Manager (CGM), NABARD
- f. Regional Director, NCDC
- g. Officers nominated by State (not more than three).



- h. SLBC Convener.
- i. State Nodal Officer- Member Secretary.

**Functions:-**

1. State level Monitoring Committee (SLMC) will implement the NIMC guidelines at the state level and provide feedback to NIMC.
2. It will also guide and steer the implementation of the scheme in the state.
3. It will set the targets as per OOMF format and review the progress regularly

**(iii)) District Level Monitoring Committee**

**Composition:-**

Following will be Members and Chairman of the DLMC:-

- a. District Collector – Chairman
- b. Chief Executive Officer of District Panchayat/CDO- Vice Chairman
- c. District Officer of Agriculture
- d. District Registrar Officers nominated Cooperative Societies
- e. Officers nominated by State (not more than three)
- f. Lead District Manager of DLBC
- g. District Manager NABARD- Member Secretary

**Functions:-**

1. District level Monitoring Committee (DLMC) The DLMC will be the first line of implementation and monitoring system within the overall framework.
2. DLMC will set targets in consultation with SLMC as per OOMF format and monitor the progress closely with the support of PMU.
3. DLMC will maintain the Dashboard in collaboration with PMU.
4. It will be responsible for the smooth implementation of the scheme and resolve any issues at the district level. In the process of sorting out implementation issues the Committee would be supported by the district administration wherever required

**Annexure-B****Tentative Allocation of Financing Facility among States/UTs**

Sl. No.	State	Financing Facility INR Crore
1	Uttar Pradesh	12831
2	Rajasthan	9015
3	Maharashtra	8460
4	Madhya Pradesh	7440
5	Gujarat	7282
6	West Bengal	7260
7	Andhra Pradesh	6540
8	Tamil Nadu	5990
9	Punjab	4713
10	Karnataka	4525
11	Bihar	3980
12	Haryana	3900
13	Telangana	3075
14	Kerala	2520
15	Odisha	2500
16	Assam	2050
17	Chhattisgarh	1990
18	Jharkhand	1445
19	Himachal Pradesh	925
20	Jammu & Kashmir & Ladakh	900
21	Uttarakhand	785
22	Tripura	360
23	Arunachal Pradesh	290

Sl. No.	State	Financing Facility INR Crore
24	Nagaland	230
25	Manipur	200
26	Mizoram	196
27	Meghalaya	190
28	Goa	110
29	Delhi	102
30	Sikkim	56
31	Puducherry	48
32	A & N Islands	40
33	Daman & Diu	22
34	Lakshadweep	11
35	Dadra & Nagar Haveli	10
36	Chandigarh	9
	<b>Total</b>	<b>1,00,000</b>





Department of Agriculture & Farmers Welfare  
कृषि और किसान कल्याण विभाग  
**National Agriculture Infra Financing Facility**

### 2.1.1 List of Documents

1. Bank's loan application form / Customer Request Letter for AIF Loan duly filled and signed
2. Passport size photographs of the promoter/partners/director
3. Identity proof – Voter ID card/PAN card/Aadhaar card/Driving license
4. Address Proof :
  - Residence: Voter ID card/Passport/Aadhaar card/Driving license/Electricity Bill/Latest property Tax Bill
  - Business Office/Registered Office: Electricity Bill/Latest Property Tax Receipt/Certificate of Incorporation in case of Companies/Certificate of Registration in ca of partnership Firms
5. Proof of Registration:
  - In case of Company : Article of Association
  - In case of Partnership : Certificate of Registration of Firm with Registrar of Firm
  - In case of MSMEs : Certificate of Registration with District Industries Centre (DIC)/Udyog Aadhar Copy
6. Income Tax Return for last three years, If available.
7. Audited Balance Sheet of last 3 Years, If available.
8. GST Certificate, if applicable.
9. Land ownership records – title deed/lease deed. If applicable, then Permission to mortgage the Immovable Property from the Lessor in case the Property is Leasehold (for primary security)
10. ROC Search Report of the Company
11. KYC documents of the promoter/firm/company
12. Copy of Bank Statement for last one year (If available)
13. Repayment track record of existing loans (Loan Statement)
14. Net Worth Statements of promoter
15. Detailed Project Report
16. As applicable - Local authority permissions, Layout plans/estimates, Building sanction